## ASSENT TO BILLS

**SECRETARY:** Sir, I lay on the Table following two Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 2nd May, 1979:—

1 The Appropriation (No. 3) Bill, 1979.

2. The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1979.

**12.42 hrs.**

## CALLING ATTETION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### REPORTED DEMONSTRATION BY RAILWAY EMPLOYEES TO PRESS THEIR DEMANDS FOR BONUS.

**श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई–उत्तर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस की अपनी मांग के समर्थन में किए गए प्रदर्शन के समाचार।"

**12.43 hrs**

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

**रेल मंत्री (प्रो॰ मधु दंडवते) :** कुछ समय पहले से रेल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा विविध मंचों से बोनस की मांग उठायी गयी है। नयी दिल्ली में आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन द्वारा रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की अपनी मांग मनवाने के लिए 7 मई को और भारतीय रेल मजदूर संघ द्वारा मान्यता के साथ-साथ बोनस दिये जाने के प्रश्न पर 8 मई को प्रदर्शन किये गये।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन ने 25 मार्च, 1979 को हुई अपनी कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल का बैलट लेने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया और अपनी सभी संबंद्ध यूनियनों को निर्देश दिया कि वे पहली मई, 1979 को बोनस और अन्य मांगों के प्रश्न पर अपने-अपने क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को 31 मई, 1979 की मध्य रात्रि से पूर्ण हड़ताल पर जाने का नोटिस दे दें। लेकिन, 29 अप्रेल, 1979 को पारित एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन ने हड़ताल को अपनी योजना को जुलाई, 1979 के अन्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन ने अपनी जनरल काउंसिल मिटिंग में 9 मई, 1979 को निर्णय किया है कि अगस्त, 1979 के अन्त तक हड़ताल के मतदान का काम पूरा कर लिया जाये और यदि इस बीच सरकार बोनस के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लेती तो उसके बाद आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेने के लिए उनकी कार्यकारी की समिति की बैठक की जायेगी।

आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कानफैडरेशन ने, जो मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, बोनस की मांग सहित एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस संगठन ने अब तक 8 मई, 1979 के 00 00 बजे से "नियमानुसार कार्य" करने का आन्दोलन शुरू कर दिया है।

रेल कर्मचारियों की दो मान्यता प्राप्त फैडरेशन—आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन तथा भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि कोई गंभीर घटनाएं नहीं हुई हैं जिनकी वजह से रेलों के परिचालन पर तुरंत प्रभाव पड़ा हो और भी क्षेत्रीय रेलों पर स्थिति लगभग सामान्य है। सरकार ने यात्री तथा माल दोनों प्रकार की गाड़ियों के सामान्य संचालन को बनाये रखने के लिए सभी संभव उपाय कर लिये हैं।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि वेतन, आय और मूल्य से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारशों तथा रेलवे जैसे सरकारी उद्यमों के कर्मचारी को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उपसमिति को कहा गया था। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

मैं रेल कर्मचारियों की यूनियनों पर यह जोर देता आ रहा हूं कि रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए इसके व्यापक निहितार्थ को देखते हुए, सरकार को पर्याप्त समय दिये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न मांगों का वार्ता द्वारा निपटारा करने का द्वार हमेशा खुला है। विगत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के माध्यम से रेल कर्मचारियों के अनेक वर्गों को फायदा पहुंचाने वाले बहुत से निर्णय किये गये हैं। जिन पर 125 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी। बोनस का प्रश्न भी इसी तरह कोई ऐसी कार्यवाही किये बिना, जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का तथा फलस्वरूप रेल कर्मचारियों के हितों का भी नुकसान हो, वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है।

**श्री मृणाल गोरे :** उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि जनता पार्टी की सरकार के आने के दो साल बाद भी रेल कर्मचारियों को बोनस के बारे में कड़े कदम उठाने पड रहे हैं। यहां 7 मई को जो हुआ, उसको मैं प्रदर्शन तो नहीं कहूंगी बल्कि लोक सभा को पेटीशन देने के लिए रेल कर्मचारी यहां पर आए थे। उन रेल कर्मचारियों की आज मन् स्थिति क्या है उसको रेल मंत्री जी जरा समझ लें, यह मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। 1974 में इसी बोनस की माग को लेकर पूरे देश में रेल कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी और उस वक्त विरोधी दल में रहने वाले जिन नेताओं ने रेल कर्मचारियों का अपनी हार्दिक सपोर्ट दी थी उनमें से कई नेता आज कैबिनेट में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में रेल कर्मचारी दो साल तक इंतजार करते रहे। जिन नेताओं ने उस समय रेल कर्मचारियों को पूरा सहकार दिया था उनमें केवल रेल मंत्री और उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फरनेंडीस ही नहीं थे बल्कि आज कैबिनेट में दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं वे भी थे—वे चाहे अटल बिहारी बाजपेयी हों, होम मिनिस्टर श्री एच० एम० पटेल हों—इन सभी लोगों ने उस समय रेल कर्मचारियों की बोनस की माग की पूरी तरह से ताईद की थी।

मेरे पास लोक सभा की 9 मई, 1974 की प्रोसीडिंग्ज हैं जिसमें इन सभी नेताओं ने पूरी तरह से बोनस की माग की ताईद की थी। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद दो साल तक रेल कर्मचारी पेशेन्स के साथ बैठे रहे। रेल कर्मचारियों को, सरकार के अधीन जो दूसरे औद्योगिक संस्थान हैं, उनके कर्मचारियों के बराबर माना जाना चाहिए – यह उनकी माग है। इसीलिए वे बोनस की माग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में यातायात सम्बन्धी जितनी भी संस्थायें हैं, जो राज्य परिवहन मण्डल हैं, उन सभी के कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यह कोई नहीं कह सकता कि रेल कर्मचारियों की बोनस की मांग वाजिब नहीं है। इस माग को लेकर 1974 में रेल कर्मचारियों ने बहुत बड़ी सैक्रीफाइस की थी। उस समय सारे देश में एकाधिकारशाही फोर्सेज के विरुद्ध लोकमत संगठित करने का काम रेल कर्मचारियों ने हड़ताल के माध्यम से किया था। आज हमें उनका धन्यवाद मानना चाहिए कि एकाधिकारशाही फोर्सेज का जो दमन चक्र रेल कर्मचारियों की हड़ताल के समय चल रहा था उसने पूरे देश की जनता का ध्यान खींच लिया था उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने एकाधिकारशाही का विरोध करने का काम किया।

यहां रेल मंत्री जी कहते हैं कि 125 करोड़ रुपये की सुविधाएं, सहायता उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को दी हैं, इस को मैं मानती हूं। इतना सब कुछ आपने किया है, मैं जानती हूं और आप ने 50 हजार कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड भी दिया है जो कई सालों से उन को नहीं मिल रहा था और आप ने दूसरी कई अच्छी बातें उन के लिये की हैं लेकिन फिर भी जो उन की बोनस की मांग है, जो उचित और सही मांग है, वह नहीं मानेंगे और उन को जब तक आप बोनस नहीं देंगे तब तक जो रेल कर्मचारी हैं, उन में शांति और पूर्ण रूप से सहयोग करने की भावना नहीं रहेगी। आप ने बार बार इस सदन में कहा है कि रेल कर्मचारी पूरी तरह से आप के साथ सहयोग कर रहे हैं। किस तरह से रेल के एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कुछ जानबूझ कर इस बात की कोशिश हो रही थी, उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप ने जगह पर रखी है और उनकी मदद से आप इस को काबू में कर सके हैं। आखिर रेल गाड़ियों को अच्छी तरह से चलाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कर्मचारियों का पूरा सहयोग आप को मिले। यह आप भी जानते हैं और मैं भी यह जानती हूं कि फेडरेशन जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस ने कुछ आन्दोलन जारी किया है लेकिन जो मान्यता प्राप्त यूनियन्स हैं उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से बहुत दिन राह देखकर अब 9 तारीख यानी कल यह फैसला किया है कि वह स्ट्राइक बैलेट ले लें और अगस्त तक वह बैलेट पूरा होने वाला है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस सवाल में पूरी तरह से जाने के लिए सब-कमेटी नियुक्त हुई थी और उस कैबिनेट कमेटी ने, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कितने महीने विचार करने के लिए ले लिये। पूरा विचार करके क्या उस ने इस प्रश्न पर निर्णय ले लिया है? जहां तक मुझे मालूम है कि उसने यह निर्णय लिया है कि बोनस देना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव कैबिनेट कमेटी ने किया है, यह सुनने में आता है। अब अगर यह बात सही है, तो फिर क्या यह बोनस देने में इतनी देर लग रही है और इस प्रश्न को लेकर आज स्थिति गंभीर बनती जा रही है। तो मैं यह कहूंगी कि रेल कर्मचारियों ने दो साल तक आप के साथ पूर्ण सहयोग किया है, उन की सहन शक्ति को अन्त तक मत ले जाइए और स्ट्राइक बैलेट होने से पहले ही इन को बोनस दीजिए और औद्योगिक कर्मचारियों के साथ उन को बराबर की परिस्थिति में लाने के लिये जो उन की माग है, उस को पूरा करिये। केवल 'विचार कर रहे हैं, इस से अब किसी का सन्तोष होने वाला नहीं है'। बहुत विचार आप कर चुके हैं। आखिर कब तक विचार करते रहेंगे। ऐसा न हो कि उन की विचार शक्ति और सहन शक्ति खत्म हो जाए। कृपया ऐसा मत करिए, और तुरन्त बोनस की माग को मंजूर कीजिए।

एक सवाल यह उठ सकता है कि अगर रेल कर्मचारियों को देंगे तो दूसरे सभी सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। मैं कहती हूं कि उस के ऊपर विचार करना है, तो वह तो आप ने जब सब कमेटी ने सुझाव दे दिया तब किया होगा। अब इस के बारे में फिर से विचार कर रहे हो? यह भी मैं कहूंगी कि बोनस देने के बाद उन से यह अपेक्षा रखेंगे कि जो पैसा उन को मिलेगा, उसमें से कुछ हिस्सा नेशनल डेवलपमेंट के लिए जाए। मैं ने इस बारे में यूनियन्स से बात नहीं की है लेकिन एक लेमैन की तरह, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, मुझे लगता है कि रेल कर्मचारी इस बात का भी आदर करेंगे लेकिन बोनस उन का अधिकार है, जिस को आप को मंजूर करना पड़ेगा। तुरन्त आप को बोनस देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक सवाल तो यह पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस का

जवाब देंगे कि उन की सहन शक्ति खत्म होने से पहले, आप का इस पर निर्णय होगा । यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं ।

**श्री राज नारायण** : मैं श्रीमती मृणाल गोरे से एक गुजारिश करूंगा कि वे यह समझ लें कि मजदूरों की 'विचार शक्ति' खत्म नहीं होगी, 'विचार शक्ति', 'कर्मशक्ति' में परिणत हो जाएगी। यह वह मान लें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप भाषा की तरमीम कर रहे हैं ।

**प्रो० मधु दंडवते** : श्रीमन्, मृणाल जी ने जो यहां भावना व्यक्त की है, उस के साथ सिर्फ मैं ही सहमत नहीं हूं बल्कि मैं समझता हूं कि सारे रेल कर्मचारी और हमारे देश के अन्य कर्मचारी भी सहमत हैं । (व्यवधान) इसलिए पहले मैं दो-तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सरकार की मार्च 1977 से लगातार यह नीति रही है कि बोनस का जो सवाल है उसको क्रमशः सटिल करने की कोशिश की जाए। एमरजेन्सी के दौरान जो बोनस कानून खत्म किया गया था उसका पुनर्स्थापित करना हमारा प्रथम चरण रहा है।

Restoration of the old Bonus Act was the first step.

यह हम लोगों ने किया । यह मैं इस सदन में ही नहीं कहता हूं बल्कि हजारों की तादाद में जहां रेल मजदूर इकट्ठे होते हैं उन के सामने भी यह कहता हूं कि क्रमशः हम को इस सवाल को हल करना है और एक मर्तबा बोनस का पुराना कानून रेस्टोर करने के बाद जितना कवरेज उस कानून में नहीं होता है उन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा । मैं जानना चाहता था कि रेल कर्मचारियों, पी एण्ड टी कर्मचारियों और डिफेंस प्रोडक्शन के कर्मचारियों, इन सभी का सवाल उठेगा । इस सवाल को हल करने में थोड़ी देर लगेगी । इस के लिये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं ।

1974 में जब इस सवाल पर स्ट्राइक किया गया था और जिसका नेतृत्व श्री जार्ज फर्नान्डीस ने किया था तो उस समय श्री जार्ज फर्नान्डीस ने श्री ललित नारायण मिश्र को तिहाड़ जेल से खत लिखा था और विरोधी दल के लोगों में से मैं भी श्रीमती गांधी से उस वक्त मिला था । उस वक्त हम लोगों ने साफ तरीके पर यह कहा था कि बुनियादी सिद्धांतों को मानने के बाद, अगर अर्थ-व्यवस्था की कोई दिक्कत हो तो फेज्ड तरीके से एक-एक मांग मान ली जाए जिस में हमारा कोई विरोध नहीं है । यह श्री जार्ज फर्नान्डीस ने संघर्ष समिति के तौर पर और विरोधी दल की ओर से मैंने खुद जाकर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय कहा था।

To quote my own words, I told the former Prime Minister that:

"Leaders of this Struggle realise that if there are financial and economic difficulties, you tell us, in a phased manner, these demands could be accepted and how the problems could be sorted out."

मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मृणाल जी को रेल मंत्री की हैसियत से रेल कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ देखने का मेरा रवैया सहानुभूति-पूर्ण रहा है । इस में गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स का सवाल आता है । इस बोनस के सवाल को हल करने में कुछ समय लगेगा । मैंने जान-बूझ कर बोनस के सवाल को अन्य सवालों से अलग कर दिया है । इस के अलावा और जितने सवाल हो सकते थे, पिछले दो सालों में हम ने उन को हल किया है । मुझे गर्व है कि जनता सरकार के आने के बाद से, पिछले दो सालों में 126 कमांड की मांगों को मंजूर किया गया है । इस को इन्टेक एफिलियेटिड आर्गेनाइजेशंस ने और विरोधी दल में काम करने वाले लोग जो यूनियनें चलाते हैं उन्होंने भी कई मर्तबा हमारे सामने कहा है कि हम यह जरूर मानते हैं कि पिछले दो साल में जितनी मांगें मंजूर हुई हैं उतनी मांगें पिछले 125 सालों के किसी भी साल का ले लीजिए, जब कि दो सालों में इतनी मांगें मंजूर नहीं हुई हैं । इतनी मांगें मंजूर करने का काम पिछली किसी भी सरकार ने 125 सालों में किसी साल में नहीं किया । हम क्रमशः इस सवाल को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं ।

अब मैं बोनस के सवाल की ओर आता हूं। जिन संस्थाओं ने बैलट का फैसला किया था—दोनों ही फेडरेशन के लोग फैसला करने के बाद मुझ से मिले थे । पहले इन्टैक एफिलियेटिड नेशनल फैडरेशन ने फैसला किया था कि पहली मई को नोटिस देंगे और 31 मई को स्ट्राइक शुरू होगी। लेकिन उस के बाद उन्होंने अपनी बैठक की और यह फैसला किया कि राज्य सभा और लोक सभा में मैंने जिस ढंग से इस सवाल को रखा था, उस पर विश्वास रख कर के हम आपको और ज्यादा समय देना चाहते हैं । यह उन्होंने मुझे लिखित पत्र में भी लिखा है ।

13.00 hrs

हमें आशा है कि आप कुछ कर पायेंगे, सरकार कुछ कर पाएगी और रेल मंत्रालय पर भरोसा रख

[प्रो॰ मधु दंडवते]

कर हम मुल्तवी रखते है । यह हमारा निर्णय है । उन्होंने स्ट्राइक का डिसिशन पोस्टपोन कर दिया है...

**श्रीमती मृणाल गोरे :** करवा नही सकते थे इसलिए पोस्टपोन किया है ।

PROF. MADHU DANDAVATE: I am coming to it. I don't want to cast any aspersion on any organisation. Here I am functioning as a Railway Minister.

AN HON. MEMBER: It is good of him.

**प्रो॰ मधु दण्डवते :** जहां तक आल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन का सवाल है उन्होंने जनरल काउंसिल में फैसला किया है कि सरकार को काफी मौका देना चाहिये । उन्होंने जो फैसला किया है वह भी हडताल करने का नहीं है । उन्होंने निर्णय यह लिया है कि 31 अगस्त तक हम बलट देंगे । आगे चल कर उन का निर्णय यह है कि 31 अगस्त तक बैलट का काम पूरा करने के बाद अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक उसके बाद बुलाएंगे और आगे चल कर क्या करना है उस के बारे में हम कारंवाई तय करेंगे । बीच में हम लोग रेल मंत्रालय के साथ बात चीत करेंगे । इस फैसले के चंद घंटों के बाद वे रेल भवन में मेरे पास आए और उन के साथ मेरी एक घंटे तक कल बैठक हुई । उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है लेकिन हम लोगो पर फिर भी आप भरोसा रखें और हमारा भी आप पर विश्वास है और हमारा विश्वास है कि स्ट्राइक की नौबत नही आएगी और जिन्होंने हमारी स्ट्राइक का नेतृत्व पुराने जमाने में किया है और जो आज सरकार चला रहे है हमारा विश्वास है कि इसको देखते हुए आप कैबिनेट के सामने, सरकार के सामने इस सवाल को रखेंगे और शायद हड़ताल करने की नौबत नहीं आएगी । उन्होंने यह भी कहा है कि हम नैगोशिएटिड सैटलमेंट के हक में हैं । *इस में गिव एंड टेक भी हो सकता है ।* इस प्रकार की नेगोशियेसन्ज स्ट्राइक बैलट से पहले हो सकती है ।

जहां तक वर्क टू रूल का सवाल है उन्होंने स्ट्राइक शुरू नहीं की है । यह गलत इनफर्मेशन लोगों की है । एक आर्गेनाइजेशन है आल इंडिया रेलवे एम्प्लायीज कनफेड्रेशन उन्होंने वर्क टू रूल, नियम के अनुसार काम करने का आन्दोलन शुरू किया है । स्ट्राइक शुरू नहीं की है । मैं किसी की नियत पर हमला नही करना चाहता हूं । लेकिन एक दो दिन गाड़ियां आने में जो दिक्कत हुई है उस का एक कारण यह भी है कि गाजियाबाद के नजदीक एक रेल एक्सीडेंट हुआ है और उत्तर प्रदेश में पावर की दिक्कत होने की वजह से ओवर हेड वायर्ज काम नहीं कर पाई है, इस लिए कुछ गडबड हो गई है । अलीगढ में कुछ गडबड़ हो गई है । उसकी वजह से गाड़ियों के आने मे कुछ देरी हुई है

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) :** हावड़ा में क्यों देरी से आ रही है ?

**प्रो॰ मधु दण्डवते :** बहुत अच्छी इनफर्मेशन आपने दी है । वर्क टू रूल शुरू होने से पहले भी हावड़ा और कलकत्ता में गाड़िया देर से आ रही थी तो इस का अर्थ यह हुआ कि वर्क टू रूल का असर नही है बल्कि दूसरे इसके कारण रहे है । वर्क टू रूल आन्दोलन आठ तारीख से शुरू हुआ है और इसको आल इंडिया रेलवेमैन फेड्रेशन, एन॰ एफ॰ आई॰ आर॰ ने स्पोर्ट नहीं दी है और ना भारतीय मजदूर संघ ने स्पोर्ट दी है । उसका कोई ज्यादा असर भी नहीं हुआ है । हम लोगो की कोशिश होगी कि वैगन मूवमेंट और पसेंजर मूवमेंट मे किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे ।

[illegible]

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कैबिनेट सब-कमेटी के सामने यह सवाल है, अर्थ मंत्रालय के साथ भी सम्पर्क हम रखे है और हमारी लगातार कोशिश होगी कि हम लोगो ने जो वादे किए हैं उन को ध्यान मे रखते हुए और रेलों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ मजदूर संस्थाओं का सहयोग ले कर और कम्प्रोमाइज करके उन की मांगों को जहां तक हो सके पूरा किया जाए । मैं माननीय सदस्या और सदन को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सवाल को नैगोशिएटिड सैटलमेंट के जरिये जल्द से जल्द हल करने की हम कोशिश करेंगे।

**श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :** मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि दो बरस मे जो उन्होंने किया है वह बहुत सराहनीय है और शायद पिछले तीस बरस मे इतना काम कभी नही हुआ है ।

श्रीमती मृणाल गोरे ने कहा कि 1974 में जो रेलवे स्ट्राइक हुई उस में माननीय मंत्री जी, जार्ज फर्नान्डीज, माननीय वाजपेयी जी, माननीय समर मुखर्जी, और बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने बोनस की मांग को रखा था पर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जैसे कोइन की दो साइड होती हैं उसी तरह से मेम्बरस की तीन साइड्स होती है एक साइड तो जब अपोजीशन में बैठता है, दूसरे जब सरकारी पक्ष में जाता है तो थोड़ा बदल जाता है, और जब मंत्री

होता है तो थोड़ा और बदलता है। और जनता पार्टी में चौथा भी हिस्सा है कि प्रधान मंत्री या उप प्रधान मंत्री होता है तो वह चौथी साइड होती है। क्योंकि यह मंत्री और बाकी लोगों में सभी साइड अलग अलग हैं। सिद्धान्त रूप में यह सरकार स्वीकार करे कि हम बोनस की मांग को स्वीकार करते हैं। लेकिन मजदूरों को साफ तौर से बता देना चाहिये कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि जिस में हम इतना खर्चा अभी कर सकें। या उस के बाद पी० ऐंड टी० के लोग, डिफेंस के लोग और कर्मचारियों के लिये इतना रुपया सरकार दे सके ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। और यह भी मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि जो अनुशासनहीनता है यह भी खत्म होनी चाहिये, और जो लोग ट्रेड यूनियन के नाम से कोहराम कर रहे हैं इस को भी सख्ती से निपटाया जाय। पिछले एक साल में देख रहे हैं कि कोयला नहीं आता, रेल वैगन नहीं हैं। अभी तक यह नहीं बता पाये कि कहानी क्या है ...

SHRIMATI AHILYA P RANGNEKAR: Employees are not responsible; trade unions are not responsible.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want that there should be strict discipline among the railway employees and they should be frankly told that they have to work hard and harder.. ..(*Interruptions*). I want the Minister to enforce discipline and the workers should be told frankly that no indiscipline would be allowed in the name of trade union or anything. There should be no harassment to the passengers; there should be no corruption. They should work hard and earn; railways should not run into losses. Then, we can consider their demand for payment of bonus. Unless they earn, they will not be allowed this. . . . (*Interruptions*). But at the same time, I would request the hon. Minister to tell them that as a matter of principle, we are for bonus, but we are not in a position to give it because that will create many complications. We have to think about P&T, Defence. . . . (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Members should have some restraint on themselves.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want to ask certain questions. Let the Minister write them down. He says, "We have taken steps to meet the situation". Suppose there is no agreement. What specific steps have Government taken, or they propose to take in future, to meet the situation. Again, is it a fact that the Finance Ministry has not accepted the demand for bonus? It has appeared in the Press that the Finance Ministry has rejected, and turned it down. Is it a fact that the Political Affairs Committee of the Cabinet has also not approved it? Thirdly, you want to have negotiations—but with whom? Will you call the representatives of all the trade unions—or of only some unions? I want that the representatives of all unions should be called. Fourthly, will this issue of bonus be applicable only to the workers working in the workshops, or even to the workers in the Railway Board? Next, what will be the financial implications, so far as Railways are concerned? If you give it, naturally you will have to give to P&T and Defence. What will be the total financial implications? I again want to repeat: the Minister should also be emphatic when he says, "Bonus, in principle, I agree. We will try to accommodate". He should be firm at the same time, because nobody should be allowed to create chaos in the country.

PROF. MADHU DANDAVATE: Before I come to the 3 or 4 questions which he has raised, let me make one thing explicitly clear. As far as indiscipline is concerned, even the organized trade unions believe that whenever they undertake any agitation, they should give proper notice. (*Interruptions*) This is not an organised trade union movement. ' You have to make a distinction between sporadic action undertaken by unorganized sections of labour and the legitimate, organized trade union activity undertaken by trade union organizations, whether they are recognized or unrecognized. There must be a distinction between the two.

[Prof. Madhu Dandawate]

Sometime back I received complaints from the Chief Ministers of Tripura and West Bengal the certain wagon movements had been affected by certain sporadic actions. We went into the problem and found that some of the sporadic actions—pinpricks as we call them—were not by any organized trade unions, but by unorganized sections. As far as such pinpricks are concerned we dealt with them very sternly, and we shall continue to deal with them very sternly. I am doing this after consultations with trade unionists, because it is not a legitimate trade union activity. Therefore, we must try to distinguish between the legitimate, organised trade union activity sponsored by the trade unions and some pinpricks and catcall actions indulged in by some irresponsible elements which belong to unorganized sections. During March last when such pinpricks were given and as a result, Tripura and West Bengal suffered the most, we took very stern and firm action; and we have made it very clear to the trade unions concerned that such pin prices would not be tolerated.

Coming to the question of bonus, the hon. Member has raised 3 or 4 questions. His first question was "In the event of any chaos created, what action will be taken". He has misunderstood our entire approach. I made it clear that I have full confidence in the trade union organisations, and I know that they have taken a decision to take a strike ballot. It will be possible for us to settle this problem across the table. Therefore, I shall not make any imaginary proposition that they are going to create chaos and we are going to deal with it. As far as sporadic actions and indiscipline are concerned, even to trade unions I have said that we shall never tolerate any indiscipline that will result in loss of productivity. As regards sensitive zones, if the coal does not reach in time, the production will suffer. In North-eastern States like Tripura and Mizoram, if the rice does not reach them in time before the monsoon, they are likely to suffer during the entire year. Therefore, any sporadic activity which will create dislocation in the economy we shall deal with it very firmly. But I shall not imagine—if a legitimate trade union strike is going to take place with due notice right from now,—what action I am going to take.

*(Interruptions)*

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will you approve strike by Government servants at all?

PROF. MADHU DANDAVATE: You are raising a very vital issue.

AN HON MEMBER: They have got a constitutional right *(Interruptions)*.

PROF MADHU DANDAVATE: As far as the present position is concerned and the constitutional provisions are concerned and all the laws that exist are concerned, there is a certain procedure prescribed by laws even for action by railway employees or any one else. They have to take a ballot, and follow it up by giving a due notice. After that there is a room for negotiations. And as far as railway employees are concerned, there are certain forums like PNM and JCM that are available; and many problems we are able to settle there. I have confidence that they will fully utilise these forums which are available; and with the machinery that is available, it will be possible to sort out a number of issues without plunging the workers into a strike action. Therefore, to your hypothetical question I do not want to give any reply.

As far as the decision taken in the matter by the Finance Ministry, the decision taken by the Cabinet Sub-Committee is concerned, the hon. Member is a knowledgeable person. He is fully equipped with the knowledge and functioning of the parliamentary democracy; and he knows it

very well, that those of us who have taken an oath of secrecy cannot leak out some of the intermediary decisions that have been taken in the Cabinet. I cannot reveal what the Sub-Committee has decided When the questions are being sorted out in the Finance Ministry, I can, however, say one thing very clearly that so far the Finance Ministry has not taken a final decision. In fact before I gave my reply in the Rajya Sabha and Lok Sabha, to the railway budget demands, I went to the Finance Minister and tried to find out from him what exactly must be the answer, and with full consultation with him, I had said that the Sub-Committee was processing the issue The Finance Ministry had to examine it; and it is at that stage the problem is there I canont reveal to this House what has happened in the Sub-Committee You understand that, but he does not realise that though he believes in that I do not want to cast aspersion on that He believes in that

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why I asked this question is because this news appeared today in a paper that the Finance Ministry is opposing it on a peculiar pretext, because it will help the urban people. That I do not want. I had no intention to ask. I had avoided it. Since you accuse me being a Member of the Ruling Party, I want to know how your Ministers are behaving; how you are behaving? How the Ministers are talking before the public I want to know, because you accuse the Members; you do not accuse the Ministers.

PROF MADHU DANDAVATE: I am not accusing.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want that there should be no strike, but there should be some sort of a forum where all the grievances of the workers should be settled.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am very sorry if my hon. friend and colleague Mr. Kanwar Lal Gupta felt that I cast any aspersion. In fact, I said that I have full faith in his knowledgeability and that he himself believes in the functioning of the parliamentary democracy. Some decisions of the Cabinet Sub-Committee, interim decisions of the Cabinet Sub-Committee, I cannot reveal.

MR. DEPUTY SPEAKER: He just took a chance in the dark.

PROF. MADHU DANDAVATE: If, inadvertenty any remarks of mine have hurt him, I would withdraw even those inadvertent remarks. So, this is the position. As far as negotiations are condemned with whom the negotiations are carried on? There are various statutory forums like JCM and PNM. There are certain recognised organisations. There was some demonstration by the Bharatiya Mazdoor Sangh claiming that they should also get the recognition. They went back happily yesterday when I assured them that even pending Industrial Relation Bill, because it will take a long time,—we have to take the consent of all, if all the existing unions whether recognised or un-recognised, accept the proposition, then as an experimental measure let us go ahead with the problem of settling the recognition issue on the basis of referendum, that is ballotted by the workers, I shall be prepared for it. I am happy to know that a number of organisations—All India Railwaymen's Federation, Bharatiya Mazdoor Sangh, they have given in writing that they are prepared for such a referendum. I hope if I am able to sort out that issue, then whether to include or whether to exclude, that issue can be eliminated. This is in connection with this.

As far as the principle is concerned he said, "Are you prepared to announce this here that we accept this in principle for Railwaymen." It means in the existing jurisdiction of

[Prof. Madhu Dandavate]

the Bonus Act if we already include Railways, then the question does not remain controversial at all. But I am not authorised to make that announcement unless the Cabinet has taken a final decision. Unfortunately, I am not accustomed to go on making pronouncement unless a final decision is taken. I shall have to await the decision. But I shall contribute my mite in settling the issue finally and firmly.

**श्री विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिणी दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सारी सिचुएशन बिलकुल नार्मल है । . . . . . (व्यवधान) . . . वर्क टू रूल के बावजूद हालात नार्मल है और कोई इस मे किसी तरह की गड़बड़ नही हो रही है । लेकिन आज के पेपर्स के अंदर जो खबरे है और खास तौर से "हिन्दुस्तान टाइम्स" के फ्रन्ट पेज पर जो खबर है, उस को आप देखे :

"

"'Sabotage' at station

Attempted sabotage by agitating railwaymen delayed all important incoming and outgoing trains here today.

Near Ghaziabad, a Bareilly-Delhi Passenger train was twice derailed The trains coming behind were delayed. Thousands of passengers were stranded.

Railwaymen were obstructing automatic signals creating confusion. The signals at some places did not operate with the result the trains did not move

Commuters crowded inquiry counters. Late this evening, lights went out for two-three minutes plunging the entire Delhi Main station in darkness creating confusion and chaos.

The platforms were strewn with luggage and commuters. The notice board said several trains were running late by three to eight hours."

अध्यक्ष महोदय, इन हालात में मंत्री महोदय का यह कहना है कि सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है और सब काम बिल्कुल ठीक , नार्मल चल रहा है कहां तक सही है ? मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि क्योंकि जो वर्क है रूल चल रहा है नार्थ ईस्टर्न एरिया में, उस की वजह से सारे हिन्दुस्तान में कोयला नही पहुंच रहा है और कोयला नहीं पहुचने की वजह हो सकता है कि हिन्दुस्तान में किसी दिन कैआटिक कंडीशन आ जाय । यह कोई साधारण बात नही है । मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हू कि जब बोनस हमें देना है और जब यह तय किया है कि बोनस की मांग को हम मानते हैं तो बोनस दिया क्यों नहीं जाता है ? उस को इतना डिले करना और इतना घुमाना फिराना जिस से यह स्थिति हो जाय कि सौ प्याज भी खाना और सौ जूते भी खाना, उन का एजीटेशन भी हो जाय और उन के झगड़े भी हो जाय और उस के बाद बोनस दें, यह कौन सी समझदारी की बात है ? समझदारी का तरीका यह है कि अगर आप को बोनस देना है तो उस से इस से पहले कि वे लोग एजीटेशन का रवैया अख्तियार करें, लाखो आदमी दिल्ली मे आए और उनके डिमान्स्ट्रेशन हो और फिर यह हो कि हम उन को बोनस देते है, बजाय इस के जब आप बोनस देने जा ही रहे है, जैसे आप डबल रोटी के कारखाने मे जो डबल रोटी बनाने वाले हैं उन को तो आप बोनस देते है गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग मे और जो रेल गाड़ी का ड्राइवर है, जो इंजन चलाता है, जिस को इतनी मुश्किल झेलनी पड़ती है, उस को आप बोनस नही दे रहे है, तो यह कोई पैरिटी की बात भी नही है और दूसरी कोई चीज भी इस मे नही है, यह सिद्धान्त रुप मे स्वीकार करने की बात नही है, आप को बोनस देना है और उस का मेथड क्या होगा, वह आप डिक्लेयर करें और उस म उन को कोई इस तरह का मौका नही देना चाहिये ।

मै यह भी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आखिर इस बात को भी वह ध्यान मे रखें कि हिन्दुस्तान में कोई पार्टी किस तरह से कैआटिक हालात पैदा कर रही है, आपने देखा कि पुलिस की हड़ताल हो रही है, आप ने यह भी देखा कि जगह जगह पर स्ट्राइकस कराने के लिए जो साजिश हो रही है । जब आप बोनस देने जा रहे है तो यह मौका क्यो देते हैं कांग्रेस (आई) के उन लोगों को, संजय गाधी और उन के दूसरे लोगो को जो सारे हिन्दुस्तान के अंदर एनार्की फैलाना चाहते है और उसका बहाना ढूंढ रहे हैं अभी जो हालत हुए और जिस तरीके से झगड़े हुआ अलीगढ के स्टडेंट्स के साथ जो हुआ, जिस के बारे मे बात आएगी, यह सब उसी साजिश का नतीजा है और मंत्री महोदय इस बात को देखें । वह कहते है कि कैबिनेट फैसला करेगी, बाद में करेगी और उस की मेथडालाजी ढूंढी जा रही है और उधर से नोटिस आ गया रेफ्रेंडम होने का तो यह क्या कोई ऐसी बात है कि हमें रेफ्रेंडम के डर से या किसी और बात से देना है या गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से देना है जब कि प्रिंसिपल के तौर पर हमने खुद इस बात को माना है । इन दोनों में बहुत फर्क है । मंत्री महोदय इस फर्क को समझें । लोगों की एजीटेशन करवा कर और करोड़ों पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचा कर बाद में बोनस का एनाउंसमेंट करेंगे.

इस का क्या फायदा है ? फौरी तौर पर एक दो दिन मे इसको कैबिनेट मे ले जायें और बोनस के बारे में डिक्लेयर करें। मैथड का फैसला बाद मे होता रहेगा। यही मै मंत्री जी से कहना चाहता हू ।

**प्रो० मधु दण्डवते :** पहले तो मै यह कहना चाहता हू कि माननीय सदस्य ने बोनस के बजाए शुरू में कोयले के वितरण का सवाल उठाया । मै इतना ही कहूगा कि जब मैंने यह कहा कि परिस्थिति नॉर्मल एबाउट नामल है, परिस्थिति सामान्य है, तो वैगन मूवमेण्ट के बारे में अन्य दिक्कतें है जिनकी वजह से कई जगह पर कोयला कम है और जहा कोयला है वहा वैगन कम हैं—इन कारणो की वजह से जो दिक्कते है उनका मैने जिक्र नही किया, मैंने कहा कि 8 तारीख को जो "वर्क टू रूल" मूवमेन्ट शुरू हुआ उसकी वजह से कोई ज्यादा डिसलोकेशन नही हुआ है। दिल्ली स्टेशन पर आज जो भीड हुई है जिसका चित्र 'टाइम्स आफ इंडिया" और दूसरे पत्रो में आया है उसका कारण वर्क टू रूल नही है । यू० पी० मे पावर की कटौती से कुछ तकलीफ पैदा हुई है या एक दो जगह पर माइनर डिरेलमेन्टस हुए (व्यवधान) मैंने वैगन्स के बारे में यह बताया कि एक दो दिन मे जो हुआ उसकी वजह अलग है । 8 तारीख को जो वर्क टू रूल मूवमेन्ट शुरू हुआ है उसका इस पर ज्यादा असर नही हुआ है।

बाद मे उन्होने कहा कि बोनस अगर देना है तो ग्रेस के साथ देना चाहिए । लम्बे अरसे तक झगडा करने के बाद जुलूस आने के बाद परिस्थिति खराब करने के बाद बोनस देना अच्छा नही है । मै उनकी भावनाओ के साथ सौ फीसदी सहमत हू । उसमें कोई दिक्कत नही है । मै बताना चाहता हू कि जल्दी से जल्दी हम फैसला कर लेंगे और जब फैसला होगा तो ग्रेस के साथ उसको लोगो के सामने रखेंगे तथा उस पर अमल करेंगे उसमे कोई दिक्कत नही होगी । जब फैसला हो जायेगा तो उस पर अमल करने में ज्यादा देर नही लगेगी । लेकिन जैसा कि और कई लोगो ने कहा, दूसरे डिपार्टमेन्ट्स का भी जिक्र करना है इन सब चीजों को देखते हुए और जो हमारे आर्थिक ससाधन है, रिसोर्सेज है उनको देखते हुए फेज मे इसको हल करना है या एक ही क्रम में हल करना है— इस पर सोचना होगा । (व्यवधान) जहा तक रेल कर्मचारियों का सवाल है बोनस पर 75 से 80 करोड का इसीडेंस होगा— पर ईयर।

AN HON. MEMBER: Per Year?

PROF. MADHU DANDAVATE: Yes. You cannot give bonus once in 50 years. It has to be given every year.

एक साल के लिए 75 से 80 करोड का खर्चा इस पर होगा ।

दूसरा सवाल जिसका जवाब मैंने नही दिया था रिट्रास्पेक्टिव जवाब देना चाहता हूं उन्होने कहा कि फैसला भी हो जाय तो वह क्या हो सकता है, क्या सिर्फ वर्कशाप में काम करने वाले ही इसमें होंगे तो उसका फैसला हमको करना पडेगा । लेकिन जब फैसला होता है तो उसमे एक ही इण्डस्ट्री में दो प्रकार के कर्मचारी कभी नही माने जाते हैं । बैंको मे और एल आई सी मे मैनअल वर्कर और दिमाग से काम करने वाले कर्मचारियो मे कोई भेद नही किया जाता है । किसी पब्लिक सेक्टर में ऐसा भेद नही किया जाता है । इसलिए जो सुझाव है वह मजूर हो या न हो लेकिन इस तरह का डिविजन कही पर नही है यह बात मैं साफ करना चाहता हू ।

**श्री अमरसिंह बी० राठवा:** (छोटा उदयपुर) आग लग जाने के बाद कुआ खोद कर पानी निकाला जाए—ऐसा हर बात में हो रहा है । आज देश मे सत्याग्रह, हडताल, डकैती, आग लगाना,—यह बाते बहुत बढ़ गई हैं। यह बाते हो जाने के बाद समितिया बनती है और उसके बाद काम शुरू करने का वचन दिया जाता है । 8 मई को बोट क्लब में रेलवे कर्मचारियो के सामने और सत्याग्राहियों के सामने उद्योगपतियो के चाहते उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि 2 माल में रेलवे कर्मचारियों के लिए और मजदूर सघ के लिए कुछ नही हुआ । यह उन के मंत्री का कहा हुआ है मै नही कह रहा हू । यह रेलवे कर्मचारियों की और उन के सघ की माग है और आप ने भी वचन दिया हुआ है कि बोनस देगे । उन्होने ये वचन दिये हुए है

(1) बोनस देने का वचन,

(2) अन्य सार्वजनिक स्थानो के समतुल्य वेतन देने का वचन ,

(3) पद मूल्याकन का वचन ,

(4) महगाई भत्ते देने का वचन ,

(5) श्रमिको को और मजदूरो का अस्थायी रखने की प्रथा को समाप्त करने का वचन ।

ये जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने भी माग की हुई है और सरकार बनने के वक्त ये वचन दिये हुए थे लेकिन ये अभी तक पूरे नही हुए हैं । कब इनको पूरा कर रहे है ?

**प्रो० मधु दण्डवते** मैं ज्यादा समय नही लूगा । एक फैरिस्त इनके सामने रखना चाहता हू कि जनता सरकार के आने के बाद रेलवे मत्री की हैसियत से कितनी मागे मजूर की है और कितना पैसा उन को दिया है । यह फैरिस्त मैं रखना चाहता हू । जहा तक श्री जार्ज फर्नाण्डीस की बात है, उन के भाषण की रपट को मैंने पढ़ा है और जिस विशाल जुलूस में जो लोग थे, उन लोगो ने भी मुझे बताया है कि जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने यह भी उन मजदूरों को बताया कि बोनस का सवाल हल होने वाला है लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जनता सरकारने उन को 126 करोड़ रुपये दिलवाए हैं । यह उन्होने उस विशाल रेली मे कहा है । यह नही कहा कि आप के सवाल हल

[प्रो० मधु दण्डवते]

नहीं हुए और जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने जो टोटल फीगर्स दिये हैं, उन का बैक ग्रप में रेलवे मंत्री की हैसियत से यहा पर देना चाहता हू ।

Selection Grade for Class IV employees, 50,000 posts, for the first time in 125 years Rs. 1.50 crores; restructuring of Class III posts, 41,000 posts Rs. 10.5 crores; revision of incentive bonus rates for workshop staff Rs. 10 crores; revision of running allowance for loco staff from 25 per cent to 40 per cent Rs. 14 crores; sancation of 2,700 posts for implementation of 10-hour rule for loco staff, which was violated by the previous Government, Rs. 2 3 crores; sanction of 10,000 additional posts for implementation of Miabhoy Award Rs. 8 crores carriage and wagon staff, upgradation of posts in ratio of 50:10:40. Rs. 6 crores, Railway workers' Classification Tribunals' Interim Report, Benefit to Artisan Staff, Rs. 10 crores Absorption of commissioned bearers as regular employees (1,012 posts) Rs. 0.3 crores; adjustment of 1974 strike absence against leave due Rs. 6 crores; 40 per cent promotion quota for Class II officers instead of 33 1/3 per cent; all temporary officers confirmed; Cadre review for Class I undertaken; dearness allowance three additional instalments; recently another instalment has been sanctioned the cost is Rs. 66 crores; Special Grant for Staff amenities Rs. 15 crores; revision of night duty allowance rates Rs. 6.8 crores; increase in rates of payment for work on National Holidays Rs. 1.23 crores; Upgradation of 7,000 Class III posts Rs. 1.75 crores.

एक खुशी की खबर मैं और देना चाहता हूं। 90 साल पहले शिकागो मे मजदूरों का एक जुलूस निकला था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नही लेना चाहिए, तो उस वक्त उन पर गोली चली थी और उन के खून से एक नया इतिहास बना और सारी दुनिया के मजदूर वक्ताओं ने कहा था 1 मई को कि 8 घंटे का दिन शुरू करें, 8 घंटे की ड्यूटी करो और इसी 1 मई को अहमदाबाद में सर्वोदय एक्सप्रेस का उदघाटन करते हुए, मैंने घोषणा की थी कि सब मे निम्न श्रेणी का जो गैंगमन है, जिन की तादाद 2 लाख 12 हजार है, उन के लिए 1 मई से 8 घंटे का दिन रहेगा ।

13.34 hrs.

## COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

### NINETEENTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to present the Nineteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers laid on the Table.

## STATEMENT *RE*. REDUCTION IN PRICES OF COTTON CLOTH AND COTTON YARN

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, Government has been viewing with concern the trend of rising prices of cotton cloth and yarn in recent months, particularly in the context of the falling prices of cotton This was first brought to the notice of the industry which in its defence pointed out that while cotton prices have, no doubt, fallen, costs of other inputs like wages, dyes and chemicals, fuel and other overheads have been increasing at the same time, which has made up for the fall in prices of cotton. The industry also drew Government's attention to the power cuts which have been imposed in various parts of the country and wage increases which have been negotiated in some major textile concentrations.

Claims of the industry were cross-checked with the experience in the National Textile Corporation and it was found that the escalation in prices was not justified by any means. I, therefore, held discussions with representatives of the textile industry in a meeting convened by me in Bombay on 10th March 1979. I urged upon the industry that they should take immediate steps for bringing down the prices of cotton cloth and cotton yarn.

Consequent upon this meeting, the Indian Cotton Mills' Federation res-